THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) Yes, Sir. The proposed museum will be housed in the barracks, where the trial of the INA personnel took place. This is awaiting formal transfer to ASI from Defence Ministry. Simultenously the ASI has initiated steps to contact National Archives, New Delhi, Netaji Research Bureau, Calcutta, Teen Murti Library, New Delhi and such other organisations to provide photographs, documents and other material for display in the proposed Museum. The related materials available in War Memorial Museum at Red Fort such as arms, amunitions, dresses and badges of army officers would also be displayed in the museum when it starts.

News paper Report on Anarchy in Irrigation Projects

*59. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item that appeared in 'The Hindustan Times' dated 8th October, 1994 under the caption 'Anarchy prevails in Irrigation Projects', wherein it has been stated that execution of these projects is tardy;

(b) if so, Government's reaction thereto and the steps Government propose to take to ensure speedy completion of these projects; and

(c) whether Government have any monitoring system about these projects; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VIDYACHARAN SHUKLA): (a) to (c) 158 major, 226 medium and 98 extension/renovation/modernisation (ERM) irrigation projects envisaging ultimate irrigation potential of 2,48,12,000 hectares and estimated to cost Rs. 65,576 crores spilled over into VIII Plan. VIII Plan outlay for these projects is Rs. 22,400 crores against an amount of Rs. 40,563 crores required for their completion. Keeping in view the project-wise VIII Plan outlay, 55 major, 98 medium and 15 ERM projects are scheduled for completion in the VIII Plan.

Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, formulated and funded by the States out of their plan resources. However, to ensure timely completion of irrigation projects, the Central Water Commission has been entrusted with monitoring of selected projects.

नागरिकों की मोटे अनाजों पर निर्भरता

*60. श्री अजीत जोगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे 40 प्रतिशत नागरिक अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए गेहूं और चावल के बजाय मोटे अनाजों पर निर्भर रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ज्वार, मक्का, बाजरा जैसे [illegible] की औसत उत्पादन [illegible] श्चित है;

(ग) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस संबंध में अनुसंधान कार्य शुरू करने की काफी संभावना है ;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मोटे अनाजों की औसत उत्पादन दर बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या इस क्षेत्र में भारत द्वारा किया जा रहा औसत व्यय अन्य विकसित देशों की तुलना में कम है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) यद्यपि कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि यह देखा गया है कि निम्न आय वर्ग के लोगों का मुख्य आहार सामान्यता मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और छोटे कदन्न हैं।

(ख) और (ग) 1992-93 के दौरान मोटे अनाजों की प्रति हैक्टेयर औसत उपज 1065 कि. ग्राम थी, जो गेहूं की 2323 कि.ग्राम और चावल की 1744 कि.ग्रा. से कम है।

(घ) से (छ) जी, हां। किसी भी फसल के उत्पादन में सुधार को हमेशा ही गुंजाइश रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा राज्य कृषि विश्व-विद्यालयों ने विभिन्न कृषि जलवायु वाली परिस्थितियों के अनुकूल मोटे अनाजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास तथा उनके लिए उचित उत्पादन प्रौद्योगिकी के बारे में अनुसंधान का काम हाथ में लिया है। इसके परिणामस्वरूप, मोटे अनाजों की उपज में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई दी है, जो 1950-51 में 408 कि.ग्राम से बढ़कर 1970-71 में 665 कि.ग्रान, 1990-91 में 900 कि.ग्राम और 1992-93 में 1065 कि.ग्राम प्रति हैक्टेयर हो गया।

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-मक्का तथा कदन्न के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास भी किए गए हैं। "समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मोटे अनाज" नामक एक केन्द्र प्रायोजित संशोधित योजना भी 1994-95 से 6 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

अन्य देशों से स्पष्ट तौर पर आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण यह सम्भव नहीं है कि इस देश में अनुसंधान पर किए जा रहे व्यय की अन्य देशों के साथ तुलना की जा सके। तथापि, सरकार ने फसलन पद्धति की नीति को अपनाकर सभी फसलों जिनमें मोटे अनाज भी शामिल हैं, की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और इस प्रक्रिया को लगभग समूचे देश में अपनाया गया है।

समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना

542. श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यान्वित की जा रही समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना के संबंध में गुजरात राज्य का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या गुजरात-सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना स्थापित करने का अनुरोध किया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) तथा (ख) जहां तक गुजरात राज्य का संबंध है, गुजरात सरकार के अनुरोध पर सहकारी विकास निगम ने सूरत, भरूच, बड़ोदरा, पंचमहल और खेड़ा जिलों में समेकित मात्स्यिकी परियोजनाओं के लिए संस्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण में दर्शाये गये है।